

भक्तिदेव देव मुखर्जी
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार,

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग,
लखनऊ, दिनांक 12 सितम्बर, 1975-

प्रिय महोदय,

सार्वजनिक उद्योगों, सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्तीय भार की वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उनके आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन में निर्दिष्ट आर्टिकल्स को सम्मिलित करने विषयक न्याय (कन्वेर्यंसिंग) अनुभाग के शासनादेश संख्या 415/सात-जी०सी०-75, दिनांक 29 जुलाई 1975 (प्रतिलिपि सुगम संदर्भ संलग्न है) का अवलोकन करें।

2—इस संबंध में मुझे आपसे यह निवेदन करने की अपेक्षा की गई है कि संबंधित सार्वजनिक उद्योग के आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन में उक्त आर्टिकल्स सम्मिलित करने के उपरान्त आप कृपया इसका सूचना सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग को भी देने का कष्ट करें।

3—जिन सार्वजनिक उद्योगों को न्याय विभाग का उक्त पत्र न भेजा गया हो, वे भी तदनुसार कार्यवाही करके, कृत कार्यवाही से इस अनुभाग को तुरन्त अवगत करा देने की कृपा करें।

सादर:

संलग्नक—न्याय विभाग का उक्त पत्र

प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उद्योगों के
प्रबन्ध निदेशकगण (नाम से)।

भवदीय,
भक्ति देव मुखर्जी।
उप-सचिव

संख्या 2332 (1) ब्यूरो/75-31 (75)/75--तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं को, न्याय (कन्वेर्यंसिंग) अनुभाग के शासनादेश संख्या 415-सात-जी०सी०/75, दिनांक 29 जुलाई, 1975 के संदर्भ में, इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने उप-विधियों में तदनुसार संशोधन करके, कृत कार्यवाही से इस अनुभाग को तुरन्त अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
भक्ति देव मुखर्जी,
उप-सचिव।